

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष – 02 अंक – 256 बेमेतरा, बुधवार 13 मई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज – 08 मूल्य – 5 रुपये डाक पंजीयन– दुर्गा/1743290201/2025–27

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली में असम और नागालैंड की 2 युवतियों से मारपीट और अभद्रता

नईदिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर पूर्वोत्तर की युवतियों से नस्लीय भेदभाव का मामला सामने आया है। इस बार नेहरू प्लेस इलाके में असम और नागालैंड की युवतियों को निशाना बनाया गया है। घटना रविवार 10 मई को बताई जा रही है। युवतियों ने आरोप लगाया कि सुबह दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के इरोस होटल के पास चाय पीते समय उनके साथ छेड़छाड़ की गई और नस्लवादी टिप्पणियां की गई। पुलिस ने युवतियों की शिकायत पर 4 युवकों की पहचान की है। पुलिस ने बताया कि रविवार शाम को एक युवती अपनी दोस्त के साथ नेहरू प्लेस में इरोस होटल के पास चाय पीने पहुंची थीं, तभी कुछ युवकों ने उन पर अश्लील और नस्लीय टिप्पणी की। युवतियों के बहस के बाद मामला बढ़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब दोनों ने मौके से निकलने की कोशिश की तो उन पर युवकों ने बांस की छड़ी से हमला किया और उनके कपड़े फाड़े।

दिल्ली में युवक की बेरहमी से हत्या

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के थाना प्रेम नगर क्षेत्र से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक दोस्त पर अपने ही दोस्त की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि मृतक को उसके ही दोस्त ने एक महिला मित्र के घर बुलाया और फिर गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान मनीष के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मनीष अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी उसके दोस्त राज का फोन आया. राज ने मनीष को अपनी महिला मित्र के घर बुलाया. मनीष अपने परिजनों को सिर्फ दस मिनट में लौटने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों की चिंता बढ़ गई. इसके बाद मनीष के पिता अपने बेटे की तलाश में निकल पड़े, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला. पूरी रात खोजबीन चलती रही. अगले दिन सुबह परिवार पर उस वक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि मनीष की गला रेतकर हत्या कर दी गई है।

मनोज कुमार अग्रवाल बने बंगाल के नए मुख्य सचिव

कोलकाता। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बता दें कि उन्होंने गत विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मनोज अग्रवाल वेस्ट बंगाल कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर उन्हीं की निगमनी में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। पश्चिम बंगाल सरकार को गौर से जारी आदेश में कहा गया, %मनोज कुमार अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, इस नियुक्ति से पहले वे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव

नीट-यूजी परीक्षा रद्द

सीबीआई करेगी पेपर लीक की जांच,इसी महीने हुआ था एग्जाम

नई दिल्ली/ एजेंसी

इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। नीट-यूजी परीक्षा-2026 रद्द हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक विवाद के कारण नीट-यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसीने कहा है कि नई परीक्षा की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। दावा किया जा रहा था कि एग्जाम के 125 सवाल हूबहू गेस पेपर से मेल खा रहे थे। इसके बाद एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। एजेंसी ने जारी बयान में कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। नई परीक्षा की तारीखें जल्द घोषित की जाएगी एनटीए ने 3 मई को

देशभर में नीट यूजी 2026 का आयोजन किया था, जिसमें पूरे देश से 22 लाख से अधिक कैंडिडेट्स नीट यूजी 2026 एग्जाम में शामिल हुए थे। एनटीए ने कहा कि 10 मई 2026 की प्रेस रिलीज के क्रम में यह फैसला लिया गया है। एजेंसी के मुताबिक, 8 मई को परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेजा गया था। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट और जांच रिपोर्ट की समीक्षा की गई। पेपर लीक होने को लेकर सीबीआई जांच के भी आदेश दिए गए। एजेंसी ने कहा कि एग्जाम सिस्टम में पारदर्शिता बनाए रखने और निष्पक्ष व विश्वसनीय परीक्षा तय करने के लिए यह कदम उठाया



गया है। एनटीए के अनुसार, अब नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नीट-यूजी परीक्षा-2026 पेपर लीक का मामला राजस्थान के सीकर से आया था। मामले की जांच राजस्थान पुलिस एसओजी कर रही है। एसओजी शुरुआत में मान रही थी कि

नीट यूजी पेपर लीक नहीं हुआ थाय़ हालांकि एसओजी ने स्वीकारा था कि नीट यूजी 2026 गेस पेपर एग्जाम से पहले वायरल हुआ था, जिससे सवाल मेन एग्जाम में आए थे। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा के प्रश्न पत्र छपने से पहले ही कुछ सवाल एक गैंग तक

पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि बायोलाॅजी के करीब 90 और केमिस्ट्री के 35 सवाल परीक्षा से पहले ही बाहर आ चुके थे। नीट एग्जाम में हूबहू यही सवाल पहले ही बाहर आ चुके थे। जबकि नीट यूजी में कुल 180 सवाल पूछे जाते हैं। एसओजी नेमामले में जयपुर से मनीष नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया हैय़ जांच एजेंसी उसे इस पूरे नेटवर्क का मुख्य संचालक मान रही है। उसके मोबाइल, कॉल रिकॉर्ड और संपर्कों को गहराई से जांच की जा रही है। अधिकारियों को आशंका है कि यह नेटवर्क सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य राज्यों में भी फैला हुआ हो सकता है।

यह केवल नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध-राहुल

नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि किसी पिता ने कर्ज लिया, किसी माँ ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला, पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफ़िश बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। उन्होंने कहा कि अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुँच से तय होगा, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा?



उदयनिधि के फिर विवादित बोल

सनातन को खत्म कर देना चाहिए-उदयनिधि स्टालिन

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और डीएमके विधायक उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सनातन, जिसने लोगों को बांटने का काम किया, उसे खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ने की संभावना है। उदयनिधि स्टालिन ने अपने संबोधन में राजनीतिक शिष्टाचार और सहयोग की भी बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उनके नेता समेत कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी थीं और यही सौहार्द विधानसभा के भीतर भी



दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग-अलग पंक्तियों में जरूर बैठते हैं, लेकिन तमिलनाडु के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। विधानसभा में उन्होंने तमिलनाडु राज्य गीत को लेकर भी नाराजगी जताई।

एनडीए के तीसरे कार्यकाल का भव्य आगाज

हिमंता बिस्वा सरमा दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली....

नई दिल्ली/ एजेंसी

असम में हिमंता बिस्वा सरमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 126 में से 102 सीटों पर कब्जा जमाया था। खास बात यह रही कि असम में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनी है। हिमंता राज्य के पहले गैर-कांग्रेसी नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला। गुवाहाटी में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री



अमित शाह समेत कई बड़े एनडीए नेता शामिल हुए। सोशल मीडिया पर भी दूसरी बार, हिमंता सरकार और,ह्रहाडुड ह्रड 3.0 तेजी से ट्रेंड करता रहा। चुनाव जीत के बाद हिमंता ने साफ कहा कि पहला

कार्यकाल सिर्फ ट्रेलर था, जबकि अब असम में विकास और बड़े फैसलों की पूरी तस्वीर दिखाई जाएगी। गुवाहाटी के खानापारा के एक मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें और उनके नए मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई। इसी के साथ राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लगातार तीसरे कार्यकाल की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा की अर्जुता नियोग, रामेश्वर तेली, अणु प्रमुख अतुल बोरा और बीपीओफ के चरण बोरो ने मंत्री पद की शपथ ली।

रुद्रप्रयाग में दो हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ क्षेत्र में अचानक मौसम खराब होने और घना कोहरा छाने एवं धुंध के कारण सोमवार को दो हेलिकॉप्टरों को एहतियातन अगस्त्यमुनि मैदान स्थित हेलिपैड पर आकस्मिक उतारना पड़ा। जानकारी के अनुसार हिमालयन हेली सेवा का एक हेलिकॉप्टर श्री बदरीनाथ से सेरसी की ओर जा रहा था जबकि इंडो कॉप्टर कंपनी का दूसरे हेलिकॉप्टर ने सहस्रधारा से फाटा के लिए उड़ान भरी थी। गुप्तकाशी एवं ऊछीमठ क्षेत्र में दृश्यता कम होने के कारण दोनों पायलटों ने यहां सुरक्षित लैंडिंग का निर्णय लिया। हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि केदार घाटी में मौसम खराब होने के कारण दोनों हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई।

योगी के नक्शे कदम पर चल पड़े सीएम सुवंदु

बंगाल में लाउडस्पीकर और सड़कों पर नमाज-पूजा बैन

कोलकाता/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल के नौवें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद सुवंदु अधिकारी अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोमवार को नब्रना में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के साथ अपनी पहली औपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर अपनी प्राथमिकाताएं स्पष्ट कर दी हैं। अधिकारी के इन शुरुआती फैसलों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सार्वजनिक



व्यवस्था और सुरक्षा को सर्वोपरि रखने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी धार्मिक आदित्यनाथ के मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां सार्वजनिक

ही, विशेष अवसरों को छोड़कर, सड़कों पर ऐसी किसी भी प्रार्थना सभा या धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे ट्रैफिक जाम हो और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। हालांकि आदेश में किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इसे सार्वजनिक स्थलों पर शांति बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस फैसले पर नखोदा मस्जिद के ट्रस्टी नासिर इब्राहिम और सर्व भारतीय प्राच्य अकादमी के प्रिंसिपल जयंत कुशारी जैसे धार्मिक नेताओं ने भी सहमति जताई है

सीएम ने की मृतकों को 5-5 लाख मुआवजा की घोषणा

सिलेंडर ब्लास्ट से एक ही परिवार के चार लोग जिंदा जले..

दुर्गा। संवाददाता

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मंगलवार दोपहर सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के चार लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में 2 बहनें, पिता और एक डेढ़ साल की बच्ची शामिल है। पूरा मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी गांव का है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक जताया है और मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए और जिला प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि सीएम के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर को इस पूरी घटना की

जांच के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बिजली खंभे में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगी। खंभे के नीचे घर के प्लास्टिक और तिरपाल से बने छपर में लगी आग फैलते हुए कीचन तक जा पहुंची, जिससे गैस सिलेंडर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि आग की लपटों ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया। घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य बाहर निकल नहीं सके और जिंदा जल गए। आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काफी फैल हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घर के अंदर से 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। घटना की सूचना पर सांसद



विजय बघेल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल, एसएसपी विजय अग्रवाल, कलेक्टर अभिजीत सिंह और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिस वक्त हादसा हुआ, उस समय घर में 2 बहनें चांदनी वैष्णव (18 वर्ष), लक्ष्मी वैष्णव (20 वर्ष) और डेढ़ साल की गोपिका

वैष्णव भी मौजूद थीं। घर में दोनों बहनों के पिता अनिल वैष्णव (45 वर्ष) भी मौजूद थे। हादसा इतना भयावह था कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के शव को पंचनामा कर पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं अनिल वैष्णव की पत्नी, बेटा और एक बेटो घर के बाहर थे, जिससे उनकी जान बच गई।

सीवरेज पाइपलाइन कार्य के दौरान धंसी मिट्टी, महिला समेत 3 मजदूरों की मौत

बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सीवरेज पाइपलाइन विस्तार कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के पुटबॉल ग्राउंड स्थित दास पान ठेला के सामने निर्माण कार्य के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे तीन मजदूर नाली में दब गए। हादसे में तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक महिला मजदूर भी शामिल है। इस घटना के बाद इलाके में अपरा-तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि बीएसपी की सीवरेज पाइपलाइन विस्तार परियोजना के तहत कार्य चल रहा था। इसी दौरान जेसीबी और चैन माउंट मशीन की मदद से खुदाई की जा रही थी। अचानक मिट्टी धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। वहीं पुलिस और बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया गया। हादसे के पीछे निर्माण कार्य में लापरवाही को वजह माना जा रहा है। फ्लिहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर, कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

संपादकीय

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में हुए चुनाव के दौरान कुल आठ सौ चौबीस सीटों पर चुनाव हुए। उनमें जीत हासिल करने वाली महिलाओं का अनुपात बेहद कम रहा। देश की सभी पार्टियां राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का एक मत से समर्थन करती हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने के लिए तैत्तीस फीसद आरक्षण का विधेयक पारित कराने में भी सभी दलों की भूमिका रही। मगर

महिलाओं की नुमाईंदगी के सवाल पर संजीदा दिखने वाली लगभग सभी पार्टियां क्या तब तक इस मुद्दे पर ठोस पहल नहीं करेंगी, जब तक विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था व्यवहार में लागू न हो जाए?आखिर क्या वजह है कि देश में लोकसभा या फिर विधानसभा के लिए जब भी चुनाव होते हैं, तो उसमें पर्याप्त संख्या में महिलाओं को टिकट देने को लेकर ईमानदार इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है? गौरतलब है कि कार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में

सभी पार्टियों की ओर से जितनी महिलाओं को टिकट दिया गया और उनमें जीतने वालों की जो संख्या रही, वह महिला भागीदारी के सवाल पर राजनीतिक दलों के प्रचारित सरोकार के प्रति ईमानदारी को कठघरे में खड़ा करती है।दरअसल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में हुए चुनाव के दौरान कुल आठ सौ चौबीस सीटों पर चुनाव हुए। उनमें जीत हासिल करने वाली महिलाओं का अनुपात बेहद कम रहा। नतीजों के मुताबिक, इन पांचों प्रदेशों में कुल पांच फीसद

सीटों पर ही महिलाएं चुनी गईं। इन राज्यों में अलग-अलग पार्टियों ने महिलाओं को टिकट देने में भी अपने घोषित सरोकारों के उलट रवैया अपनाया। मसलन, पश्चिम बंगाल में दो सौ सात सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आने वाली भाजपा ने सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उसने सिर्फ तैत्तीस सीटों पर महिलाओं को मौका दिया था।जबकि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी के 291 सीटों में से 52 महिलाओं को टिकट दिया था। नतीजतन,

राज्य की कुल सीटों में से सिर्फ दस फीसद महिलाएं जीत सकीं। दूसरी ओर, तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ, जहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके 234 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसने सिर्फ चौबीस महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था। असम में फिर से जीतने वाली भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 126 सीटों में से केवल छह महिलाओं को टिकट दिया। केरल में जीत हासिल करने वाली यूडीएफ ने सिर्फ दस महिलाओं को मौका दिया।जाहिर है,

तकरीबन सभी पार्टियों ने महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। हालांकि हाल ही में संसद में परिसीमन विधेयक पारित न होने के संदर्भ में महिला आरक्षण का सवाल चुनावी राजनीति का भी मुद्दा बना और भाजपा की ओर से इस मसले पर विपक्षी दलों पर सवाल उठाए गए। विर्डबना यह है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के घोषित दावों के बरक्स टिकट देने के मामले में भाजपा सहित सभी पार्टियों के भीतर इच्छाशक्ति की कमी दिखती है।

अस्पताल या इंतजार केंद्र? इलाज से पहले ही थका देती है व्यवस्था, बिस्तरों की कमी ने बढ़ाई मुश्किल

देश के अस्पतालों में प्रति एक हजार लोगों के लिए औसतन 1.3 बिस्तर हैं, जबकि दुनिया का मानक इससे दोगुने से भी ज्यादा है । इससे स्पष्ट है कि मरीज ज्यादा हैं और जगह कम है । अस्पताल उपचार का केंद्र होते हैं, लेकिन कई बार वे खुद ही बीमार नजर आते हैं । यह कहने और सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन देश के स्वास्थ्य तंत्र की इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता । जिन स्वास्थ्य संस्थानों पर हम जीवन बचाने का भरोसा करते हैं, वही कई बार संसाधनों की कमी, प्रबंधन की विफलता और बढ़ती व्यावसायिकता की वजह से संकट का कारण बन जाते हैं । ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ज्यादा दबाव है, या फिर इसे खुद इलाज की जरूरत है ।

(मनीष जैसल)

आज के दौर में अस्पताल जाना कई बार बीमारी से बड़ा अनुभव बन जाता है। मरीज इलाज के लिए अस्पताल जाता है, लेकिन सबसे पहले उसे भीड़ और कतार में खड़े होकर कई घंटे इंतजार करने की परेशानी से जूझना पड़ता है। इसके बाद कहीं बिस्तर नहीं मिलता, तो कहीं विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद नहीं होते। यही नहीं, कई बार सब कुछ होने के बावजूद व्यवस्था साथ नहीं देती। यह तस्वीर किसी एक शहर की नहीं, बल्कि देश भर की है।

देश के अस्पतालों में प्रति एक हजार लोगों के लिए औसतन 1.3 बिस्तर हैं, जबकि दुनिया का मानक इससे दोगुने से भी ज्यादा है। इससे स्पष्ट है कि मरीज ज्यादा हैं और जगह कम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या और साफ दिखती है, जहां आबादी इतनी ज्यादा है कि अस्पताल हमेशा भरे रहते हैं। समय के साथ आबादी बढ़ी, मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके अनुरूप अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (एनएचपी-2022) के अनुसार, देश में प्रति दस हजार आबादी पर अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता लगभग पंद्रह है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार न्यूनतम संख्या तीस बिस्तरों की है। यानी हम बुनियादी स्तर पर अभी आधे रास्ते में हैं। राज्यों के बीच असमानता इस संकट को और गहरा करती है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं अपेक्षाकृत बेहतर हैं, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थिति गंभीर है। बिहार में प्रति दस हजार आबादी पर बिस्तरों की संख्या छह-सात के बीच है। इसका मतलब है कि एक ही देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता नागरिक की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस 2022-23) की रपट से पता चलता है कि देश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 70 फीसद से अधिक पद खाली हैं। कई बड़े राज्यों में यह आंकड़ा 75-80 फीसद तक है। यानी ग्रामीण भारत में रहने वाले करोड़ों लोग प्राथमिक स्तर पर ही विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं से वंचित हैं।

अस्पतालों में संक्रमण की स्थिति भी चिंताजनक है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, देश में 10-15 फीसद मरीज इलाज के दौरान ही संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। विकसित देशों में यह आंकड़ा लगभग आधा है। यानी हमारे अस्पताल कई बार रोग से मुक्ति के बजाय नई बीमारी का केंद्र बन जाते हैं। कोविड-19 महामारी ने इस सच्चाई को सबके सामने रखा। आक्सीजन की कमी, गहन चिकित्सा इकाई में बिस्तरों का अभाव और अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें, ये दुश्चर केवल एक आपदा नहीं, बल्कि हमारी तैयारियों की कमी का परिणाम थे।

निजी अस्पतालों की भूमिका भी सवालों से परे नहीं है। इलाज की बढ़ती लागत और पारदर्शिता की कमी ने आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा को महंगा एवं जटिल बना दिया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 65 फीसद और शहरी क्षेत्रों में 70 फीसद लोग निजी अस्पतालों का सहारा



लेते हैं। यह केवल सुविधा नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था पर घटते भरोसे का संकेत है।

देश में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:1400 के आसपास है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और खराब है। नर्सिंग स्टाफ की कमी और उपकरणों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। केग की रपटों में पाया गया है कि कई अस्पतालों में महंगे उपकरण या तो खराब पड़े रहते हैं या उनका उपयोग नहीं हो पाता। यानी समस्या संसाधनों की कमी के साथ-साथ उनके प्रबंधन की भी है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, भारत में प्रतिदिन 700 टन से अधिक जैव-चिकित्सीय कचरा उत्पन्न होता है, जिसका पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं हो पाता। यह स्थिति संक्रमण के खतरे को और बढ़ाती है।

इन चुनौतियों के बीच वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था- गरीब और कमजोर वर्ग को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना। यह योजना अपनी अवधारणा में बेहतर थी और इसने लाखों लोगों को पहली बार बड़े अस्पतालों तक पहुंचने का अवसर दिया। मगर जैसे-जैसे इसका विस्तार हुआ, वैसे-वैसे इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आने लगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की जांच में पाया गया कि कई अस्पतालों ने फर्जी मरीज दिखाकर या अनावश्यक प्रक्रियाएं जोड़कर इस योजना के तहत धनराशि के दावे किए। ऐसे मामलों में सैकड़ों निजी अस्पतालों को अनियमितताओं के कारण इस योजना से बाहर कर दिया गया।

ऐसे मामलों का मानवीय पक्ष अधिक असहज करता है। एक सीमित आय वाला परिवार आयुष्मान कार्ड के भरोसे निजी अस्पताल पहुंचता है और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। सतह पर सब कुछ सामान्य दिखता है, मगर बाद में कई बार सामने आता है कि अस्पताल की ओर से मरीज के इलाज के दौरान जिन प्रक्रियाओं का दावा किया गया, वे हूँ ही नहीं। यानी अस्पतालों के

लिए उपचार की गुणवत्ता से इतर, खर्च के बिल का विस्तार प्राथमिकता बन जाता है।

देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता भी स्पष्ट दिखाई देती है। लगभग 65 फीसद आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकों का बड़ा हिस्सा शहरों में केंद्रित है। इस प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बर्बादी के साथ-साथ कई बार मरीज की स्थिति भी गंभीर हो जाती है।

दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद अत्यधिक भीड़ और दबाव के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यह असमानता केवल सुविधा की कमी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच के अभाव को दर्शाती है।

देश में स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित होता है, जबकि सरकारी अस्पतालों पर गरीब और निम्न आय वर्ग की निर्भरता अधिक है। अनुमानतः 60 से 70 फीसद मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं, जहां सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर होती हैं, लेकिन खर्च अधिक होता है। इसके विपरीत, सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता या निःशुल्क होता है, लेकिन वहां संसाधनों की कमी और अत्यधिक भीड़ के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति एक ऐसी दोहरी व्यवस्था को जन्म देती है, जहां इलाज की गुणवत्ता व्यक्ति की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती है और यह स्वास्थ्य सेवाओं की समानता और न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसे में अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और मानव संसाधनों की कमी को दूर करना प्राथमिक कदम होने चाहिए। इसके साथ ही डिजिटल निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

देश का नया अन्न भंडार बनता मध्यप्रदेश

पंजाब-हरियाणा के वर्चस्व को चुनौती, किसान हितों की नई राजनीति गढ़ रहे डॉ.मोहन यादव

कृष्णमोहन झा

देश में जब भी सरकारी गेहूं खरीदी की चर्चा होती थी तो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा का नाम लिया जाता था। हरित क्रांति के बाद इन दोनों राज्यों ने दशकों तक देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ के रूप में अपनी भूमिका निभाई। बाद के वर्षों में राजस्थान और उत्तरप्रदेश भी इस व्यवस्था का हिस्सा बने, लेकिन आज जिस राज्य ने सबसे तेज़ी से अपनी स्थिति मजबूत की है, वह मध्यप्रदेश है।

10 मई 2026 तक मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे केवल प्रशासनिक सफलता की कहानी नहीं कहते, बल्कि यह संकेत भी देते हैं कि प्रदेश अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का नया केंद्र बनता जा रहा है।

अब तक राज्य में 14 लाख 82 हजार 865 स्लॉट आरक्षित किए जा चुके हैं। 10 लाख 959 किसानों ने अपनी उपज बेची है। कुल 63 लाख 19 हजार 675 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। राज्य की अधिकतम खरीदी क्षमता 1 करोड़ 22 लाख 28 हजार 122 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। किसानों को अब तक 11 हजार 623 करोड़ 43 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। केवल एक दिन पहले ही *55 हजार 380 किसानों से 4 लाख 86 हजार 368 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।

इन आंकड़ों की तुलना यदि अन्य राज्यों से की जाए तो मध्यप्रदेश की उपलब्धि और अधिक स्पष्ट हो जाती है। पंजाब में इस वर्ष लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और वह अभी भी देश में शीर्ष पर है। हरियाणा में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन के आसपास खरीदी हो रही है। राजस्थान का लक्ष्य लगभग 21 लाख मीट्रिक टन है, जबकि उत्तरप्रदेश लगभग 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास

है। बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सरकारी गेहूं खरीदी बेहद सीमित है।

स्पष्ट है कि पंजाब के बाद यदि कोई राज्य सबसे तेज़ी से अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है तो वह मध्यप्रदेश है।



पहले केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के लिए 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के लगातार प्रयासों के बाद यह लक्ष्य बढ़ाकर एक करोड़ मीट्रिक टन* कर दिया गया। यह केवल आंकड़ों में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार को मध्यप्रदेश की कृषि क्षमता और यहां की खरीदी व्यवस्था पर भरोसा है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री केवल बैठकों और घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं। वे लगातार खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। खरीीन के कतरगांव से लेकर शाजापुर के मकौड़ी तक उनका अचानक पहुंचना यह संदेश देता है कि सरकार किसान हितों के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं करेगी।

उन्होंने स्वयं तौल व्यवस्था देखी, बारदाने की उपलब्धता की समीक्षा की, किसानों से सीधा संवाद किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी अवधि बढ़ाने का निर्णय भी इसी संवेदनशीलता को दर्शाता है।

यह सक्रियता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्यप्रदेश वर्ष 2017 के मंडसौर किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव को भूल नहीं सकता। उस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसान केवल घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होता। उसे समय पर खरीदी, समय पर भुगतान और सम्मानजनक व्यवहार चाहिए।

मोदी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को बढ़ा हुआ खरीदी लक्ष्य दिया जाना और राज्य सरकार की लगातार जमीनी निगरानी यह दर्शाती है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय है।

आज जब कई राज्यों में किसान खरीदी व्यवस्था को लेकर शिकायत कर रहे हैं, तब मध्यप्रदेश एक सफल मॉडल के रूप में उभर रहा है। यदि यही गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश केवल देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सरकारी गेहूं खरीदी राज्य भी बन सकता है।

यह केवल कृषि क्षेत्र की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व की एक बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक सफलता के रूप में भी दर्ज होगी।

तुलसी की माया

पूरी कॉलोनी में तुलसी के काम की चर्चा बनी रहती। कालोनी की सभी महिलाएं चाहतीं, तुलसी मेरे घर काम करने लगे। पर वाह रे तुलसी, महीने में छः दिन का गोल ऐसे ही मार देती।

कभी –कभी महीने में छः दिन ही काम पर आती तब भी कोई उसे अपने घर से काम से अलग नहीं करता।

छुट्टी मारने की उसकी अदा को कोई भांप नहीं सकता। उसकी हर चाल में सम्मोहन रहता जो सीधे घर मालकिन पर ही असर करता। किसी भी घर के पुरुष की यह हिम्मत नहीं रहती कि तुलसी के विपरीत दो शब्द कंट से निकल जाए।

इन सब के बावजूद कॉलोनी में तुलसी का आकर्षण बना रहता। उसमें कोई विशेष योग्यता नहीं फिर भी अपने व्यवहार के कारण वह लोकप्रिय हो चुकी थी। उसके मीठे बोल सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते। जीवन उतार –चढ़ाव की ही नाम है। किसी रूप में धन कमाने को चाहत हर व्यक्ति में निहित रहन मनुष्य की जीवंत प्रवृत्ति का हिस्सा है। इसी चाह में तुलसी एक कम्पनी में अभिकर्ता बनती है और बिजनेस चैनल बनाने को आतुर हो जाती है। अब वह उसी कार्य में व्यस्त रहने लगी। अपने सगे, परिचितों से मिलकर अपनी आय को बढ़ाने की जद्दोजहद में कॉलोनी में बनी उसकी साख पर विपरीत प्रभाव होने लगा। वह कहीं – कहीं कर्ज लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने का यत्न करने लगी थी।पहले उसकी स्फूर्ति, मीठे बोल और किसी काम को ना नहीं कहने की उसकी प्रवृत्ति उसकी खूबसूरती थी, जिसकी कायल कॉलोनी की हर महिला थी। तुलसी अब जीवन की हलती शाम की तरह हो चुकी थी।

वही तुलसी जिसकी माया हमेशा बनी रही, वह धीरे –धीरे विलुप्त होने लगी। व्यावहारिक रूप में उसकी साख समाप्त हो चुकी थी। लोग व्यक्ति का वही रूप पसंद करते हैं, जो उनके लिए सुविधाजनक होता है।

गजेंद्र बख्शी

रिद्धि- सिद्धि कॉलोनी

राजनांदगांव

समर कैप और गैर शिक्षकीय कार्यों के विरोध में शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन, शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने उठाई मांग, कहा- भीषण गर्मी में बच्चों और शिक्षकों पर बढ़ रहा दबाव



बीजापुर/मूक पत्रिका

भीषण गर्मी के बीच समर कैप और ब्रिज कोर्स संचालित किए जाने के विरोध में शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिले के विभिन्न शिक्षक संगठनो ने नवपदस्थ कलेक्टर विश्वदीप

अवैध उत्खनन से परेशान ग्रामीण, कार्रवाई सिर्फकागजों तक सीमित

कटंगपाली/मूक पत्रिका

सारंगढ़ बिलाईगढ जिले में ऐसे बहुत प्रभावित गांव है जहां लोग आज भी आजादी के पूर्व की जीवन जैसे जीने को मजबूर है। बड़ी बड़ी बीमारियों का चंगुल में फंस्ते जा रहे है। वही बरमकेला क्षेत्र के साल्हेओना और कटंगपाली गांव में अवैध उत्खनन का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। पत्थर खदानों में नियमों को ताक पर रखकर हो रहे अवैध उत्खनन से आम जनमानस बेहद परेशान है। धूल, प्रदूषण और भारी वाहनों की आवाजाही ने ग्रामीणों का जीवन मुश्किल बना दिया है।ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन



अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी केवल कागजी खानापूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं।स्थानीय लोगों के अनुसार, अवैध खनन माफिया दिन-रात बेखोफ उत्खनन में लगे हुए हैं, जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। खेतों की उपजाऊ भूमि प्रभावित हो रही है और आसपास के

क्षेत्रों में दररों तक देखने को मिल रही हैं।ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई, तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कब तक ठोस कदम उखता है या फिर कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी।

वाडला पंचायत में लगा चलित थाना, ग्रामीणों को किया जागरूक साइबर अपराध, पॉक्सो और यातायात नियमों की दी जानकारी



बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। भोपालपटनम थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत वाडला में मंगलवार को चलित थाना लगाकर ग्रामीणों को कानून, साइबर सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी जानकारीयां दी गई। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव के मार्गदर्शन में

आयोजित किया गया। इसमें वाडला के साथ-साथ पोलेम, मड्रीमरका और पेटाबोगरा गांव के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।पुलिस विभाग द्वारा बोते कुछ दिनों से लगातार अलग-अलग ग्रामीण इलाकों में चलित थाना और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि दूरस्थ गांवों तक पहुंचकर लोगों को कानून, सुरक्षा और शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा सके।कार्यक्रम में

ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है। साथ ही शिक्षकों के लिए भी 1 मई से 16 जून तक अवकाश लागू किया गया है। इसके बावजूद जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से समर कैप और ब्रिज कोर्स संचालित कर बच्चों को स्कूल बुलाना जा रहा है तथा शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है।संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि तेज गर्मी में बच्चों से खेल, योग, डांस जैसी गतिविधियां कराना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उन्होंने आगे बताया कि शिक्षकों से पहले से ही जनगणना, तेंदूपत्ता, बस्तर मुन्ने और अन्य गैर शिक्षकीय कार्य कराए जा रहे हैं। कई शिक्षकों को एक साथ दो से तीन जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा है।शिक्षकों ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में गर्मी और तनाव के कारण दो शिक्षक गंभीर रूप से बीमार हुए, जिनमें ब्रेन हेमरेज और मृत्यु जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। इसके बावजूद समर कैप और ब्रिज कोर्स के आदेश जारी करना शिक्षकों के लिए चिंता का विषय है। संघ ने प्रशासन से मांग की है कि समर कैप और ब्रिज कोर्स को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। मांग पूरी नहीं

होने पर राज्य संगठन, उच्च अधिकारियों और सचिवालय स्तर पर शिकायत करने की चेतावनी भी दी गई है।ज्ञापन सौंपने के दौरान कामेश्वर दुब्बा, कैलाश रामटेके, राजेश मिश्रा, बृजलाल पूजारी, महेश यालम, रमन झा, विजय चापड़ी, सुरेश गोटा, प्रदीप साहनी, नागेश गोरला, मोहसिन खान, पुरुषोत्तम कुडमूल, बीरा रामचंद्रम, रमेश कारम, हितेंद्र दुर्गम सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

मुख्य मांगें

समर कैप और ब्रिज कोर्स तत्काल बंद किया जाए गर्मी में बच्चों को स्कूल बुलाने पर रोक लगे शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य लेना बंद हो शासन के ग्रीष्मकालीन अवकाश आदेश का पालन किया जाए

शिक्षकों ने क्या कहा

-भीषण गर्मी में लगातार फ़ैल्ड ड्यूटी और अतिरिक्त जिम्मेदारियों से शिक्षक मानसिक दबाव में हैं। ऐसे समय में समर कैप चलाना उचित नहीं है।-

जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण शुरू, अच्छी गुणवत्ता पर मिलेगा बोनस

संग्राहकों को बीमा और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति का भी लाभ



बीजापुर/मूक पत्रिका

जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण अभियान की शुरुआत हो गई है। जिला वनोपज सहकारी यूनियन बीजापुर के अंतर्गत 28 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में

संग्रहण कार्य शुरू किया गया है। जिले के 45 तेंदूपत्ता लॉटों के 582 पट्टों में इस साल खरीदी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पामेड़, उमूर, हीरापुर, चेरामंगी, कोरसागुड़ा, ईलमिड़ी, देपला, भद्रकाली, सकनापल्ली, चेरपल्ली, मददेड़, बंदेपारा, पामगल, धनोरा, संतोषपुर,

तोयनार, गुदमा, बरदेला, माटवाड़ा, भैरमगढ़, कोडेली, मिरतुर, कुटूर और करकेली समेत विभिन्न समितियों के तहत संग्रहण कार्य संचालित किया जा रहा है।शासन द्वारा तय दर के अनुसार ग्रामीणों से 5.50 रुपए प्रति गड्ढी और 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से

सुशासन का असली चेहरा .. भोजन के लिए जनता के साथ कतार में खड़े नजर आए अधिकारी

घरघोड़ा/मूक पत्रिका

प्रशासनिक आयोजनों में अक्सर अधिकारियों और आम जनता के बीच दूरी देखने को मिलती है, लेकिन घरघोड़ा के घरघोड़ी में आयोजित सुशासन लोहार ने इस धारणा को बदलने का काम किया। यहां प्रशासन की ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने हजारों ग्रामीणों का दिल जीत लिया। अधिकारियों की सादगी, सहजता और जनता के प्रति अपनापन पूरे आयोजन का सबसे चर्चित पहलू बन गया।11 मई को आयोजित इस सुशासन लोहार में क्षेत्र के हजारों ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने तथा जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए अलग-अलग विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं, जिनका मौके पर ही निराकरण करने का प्रयास किया गया।कार्यक्रम का सबसे भावुक



और सराहनीय दृश्य उस समय देखने को मिला, जब एसडीएम घरघोड़ा दुर्गा प्रसाद अधिकारी, तहसीलदार मनोज कुमार गुप्ता एवं शिवम पाण्डेय, नायब तहसीलदार सहदेव पैकरा तथा जनप्रद पंचायत सीईओ विनय चौधरी सहित अन्य अधिकारी आम लोगों के साथ भोजन की लाइन में खड़े नजर आए। न कोई विशेष व्यवस्था, न कोई वीआईपी संस्कृति अधिकारीगण भी आम नागरिकों के साथ कतार में लगे, भोजन लिया और भोजन किया। अधिकारियों की यह सादगी और व्यवहार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। ग्रामीणों ने कहा कि पहली बार किसी बड़े प्रशासनिक आयोजन में अधिकारियों को इतने सहज

और सामान्य रूप में देखा गया। इससे प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास और अपनापन और अधिक मजबूत हुआ है। सुशासन लोहार में भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की गई थी। प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना नहीं, बल्कि जनता से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझना और समाधान देना भी था। घरघोड़ा में देखने को मिली यह तस्वीर केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि संवेदनशील प्रशासन, सादगीपूर्ण नेतृत्व और जनता के साथ बढ़ते विश्वास की एक सकारात्मक मिसाल बनकर सामने आई।

विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) : वीबी–जी राम जी (विकसित भारत–जी राम जी) अधिनियम, 2025

बेमेतरा/मूक पत्रिका

विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य मजदूरी आधारित रोजगार को सतत विकास तथा विकसित भारत ३2047 के विजन के साथ जोड़ते हुए ग्रामीण रोजगार ढांचे (फ्रेमवर्क) में परिवर्तन लाना है। यह अधिनियम सभी ग्रामीण परिवारों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। यह ढांचा परिणामोन्मुख कार्यों तथा डिजिटल रूप से एकीकृत योजना के माध्यम से जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका परिसंपत्तियों और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को प्राथमिकता देता है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-रेफ़ेसिंग, डिजिटल निगरानी तथा समयबद्ध मजदूरी भुगतान के माध्यम से तकनीक-सक्षम प्रशासन (गवर्नेंस) का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। अनिवार्य सोशल ऑडिट, संरचित निगरानी तंत्र और शिकायत निवारण प्रणाली इसके क्रियान्वयन को और सशक्त बनाते हैं। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को सतत ग्राम विकास और स्थायी परिसंपत्ति निर्माण के एक उत्पादक प्रेरक के रूप में स्थापित करता है।

देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत-जी



राम जी अधिनियम का ऐतिहासिक क्रियान्वयन– भारत सरकार ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 01/07/2026 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के लागू होने के साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 उसी तिथि से निरस्त हो जाएगा। यह भारत के ग्रामीण विकास के प्रेमवर्क में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जो विकसित भारत३2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप एक समेकित(इंटीग्रेटेड), भविष्य उन्मुख एवं उत्पादकता(प्रोडक्टिविटी) आधारित ग्रामीण परिवर्तन के नए युग का शुभारंभ करता है। इस अधिनियम का लागू होना

पूर्ववर्ती महात्मा गांधी नरेगा व्यवस्था से एक आधुनिक ग्रामीण विकास संरचना की ओर ऐतिहासिक ट्रांजिशन का संकेत है, जो आजीविका सुरक्षा, स्थायी परिसंपत्ति निर्माण, तकनीक-सक्षम प्रशासन, कन्वर्जेंस-आधारित योजना और जलवायु अनुकूलनता को एक साथ जोड़ती है।यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य सतत ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की अपेक्षा है। साथ ही, इसका उद्देश्य ऐसी स्थायी और उत्पादक ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना है, जो जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, स्थानीय आर्थिक विकास और जलवायु संबंधी चुनौतियों के विरुद्ध अनुकूलनता को मजबूत करे।

पृष्ठभूमि और सुधार की आवश्यकता

कई दशकों से मजदूरी-आधारित रोजगार कार्यक्रम भारत की ग्रामीण विकास रणनीति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने अल्प-रोजगार और आजीविका असुरक्षा का सामना कर रहे ग्रामीण परिवारों को आय सहायता प्रदान की

है।समय के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार, भौतिक और डिजिटल संर्पर्क में सुधार, वित्तीय समावेशन की वृद्धि और आजीविका के विविधीकरण के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों ने वर्तमान ग्रामीण रोजगार के प्रेमवर्क को सम्मकालीन आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और विकसित भारत३2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप पुनर्संतुलित करने की आवश्यकता उत्पन्न की है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आजीविका गारंटी के प्रेमवर्क को मजबूत करने हेतु वैधानिक रोजगार गारंटी को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है। इस बड़ी हुई गारंटी का उद्देश्य ग्रामीण विकास की तीव्र गति को समर्थन देना, अधिक आय सुरक्षा प्रदान करना और विस्तारित रोजगार अवसरों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाना है। तदनुसार, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) : वीबी३जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 नामक एक नया कानून बनाया गया है, ताकि विकसित भारत३2047 के विजन के अनुरूप आजीविका सुरक्षा को उत्पादकता, कन्वर्जेंस, अनुकूलनता और सतत परिसंपत्ति निर्माण के साथ एकीकृत करने वाला भविष्य-उन्मुख ग्रामीण विकास प्रेमवर्क स्थापित किया जा सके।विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 एक व्यापक विधायी पुनर्संरचना है, जिसे ग्रामीण रोजगार को

विकसित भारत३2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप बनाने के लिए तैयार किया गया है। संसद द्वारा दिसंबर 2025 में पारित यह अधिनियम दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 का स्थान लेता है। यह ग्रामीण रोजगार को एक स्वतंत्र कल्याणकारी हस्तक्षेप से आगे बढ़कर विकास और अनुकूलन आधारित अवसंरचना के एक समेकित साधन के रूप में स्थापित करता है।

बेहतर आजीविका गारंटी और श्रमिक-केंद्रित फ्रेमवर्क

इस अधिनियम की एक केंद्रीय विशेषता सभी ग्रामीण परिवारों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह बड़ी हुई गारंटी आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने, आय की स्थिरता में सुधार करने, ग्रामीण उपभोग को समर्थन देने और कमजोर परिवारों को अधिक आर्थिक अनुकूलनता प्रदान करने के उद्देश्य से है। यह प्रेमवर्क -रोजगार भी, सम्मान भी- के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि ग्रामीण श्रमिक दीर्घकालिक ग्राम विकास में योगदान देने

वाली स्थायी और उत्पादक सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनें। महात्मा गांधी नरेगा से नई व्यवस्था में ट्रांजिशन को भी निर्बाध एवं श्रमिक-अनुकूल बनाया गया है। वर्तमान ई-केवाईसी सलापित जाँब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे, जब तक ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। जिन श्रमिकों के पास वर्तमान में जाँब कार्ड नहीं हैं, वे ग्राम पंचायत स्तर पर पंजीकरण और नए कार्ड जारी कराने हेतु आवेदन कर सकते हैं। केवल लॉकड ई-केवाईसी के कारण किसी भी श्रमिक को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा, तथा आवश्यक होने पर कार्यस्थलों सहित ई-केवाईसी पूर्ण कराने हेतु सुविधा तंत्र उपलब्ध कराया गया है।

श्रमिक मौखिक रूप से, मौजूदा फॉर्म-6 व्यवस्था के माध्यम से लिखित रूप में अथवा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार की मांग जारी रख सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, अन्यथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे। बेरोजगारी भत्ता वित्तीय वर्ष के पहले तीस दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के कम-से-कम एक-चौथाई तथा शेष अवधि के लिए कम-से-कम आधी मजदूरी दर के बराबर देय होगा। इससे रोजगार की कानूनी गारंटी और क्रियान्वयन ढांचे की जवाबदेही और मजबूत होगी।

